Political Party
Polity By : Karan Sir

National Party (राजनीतिक पार्टियां)			
Sl. No.	**Name of the Party (Abbreviation)**	**Founder Name**	**Year of Formation**
1.	Bharatiya Janata Party (BJP) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)	A.B. Vajpayee and L.K. Advani अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवानी	1980
2.	Indian National Congress (INC) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी)	A.O. Hume ए. ओ. ह्यूम	1885
3.	Bahujan Samaj Party (BSP) बहुजन समाज पार्टी (बसपा)	Kanshi Ram कांशीराम	1984
4.	Communist Party of India (Marxist) (CPM) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीएम)	Jyoti Basu EMS Namboodiripad Hare Krishna Konar ज्योति बसू ई.एम.एस नांबिरिपद हरे कृष्ण कोनार	1964
5.	Aam Aadmi Party (AAP) आम आदमी पार्टी	Arvind Kejriwal अरविंद केजरीवाल	2012
6.	National People's Party (NPP) नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी)	P.A. Sangma पी.ए. संगमा	2013

Regional Party (क्षेत्रीय पार्टियां)			
Sl. No.	**Name of the Party (Abbreviation)**	**Founder Name**	**Year of Formation**
1.	Shiromani Akall Dal (SAD) शिरोमणि अकाल दल (एस.ए.डी.)	—	1920
2.	Jammu & Kashmir National Conference (JKNC) जम्मू एवं कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन (जेकेएनसी)	Sheikh Abdullah शेख अब्दुल्लाह	1939
3.	Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके)	C.N. Annadural सी.एन. अन्नादुरल	1949
4.	Communist Party of India (CPI) कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई)	M.N. Roy एम.एन.रॉय	1925
5.	Shiv Sena (SHS) शिव सेना (एसएचएस)	Bal Thackeray बाल ठाकरे	1966
6.	All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके)	M.G. Ramachandran एम.जी. रामचंद्रम	1972
7.	Telugu Desam Party (TDP) तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी)	N.T. Rama Rao एन.टी रामाराव	1982
8.	Asom Gana Parishad (AGP) असम गण परिषद (एजीपी)	P.K. Mahanta पी.के. महांता	1985
9.	Samajwadi Party (SP) समाजवादी पार्टी (एसपी)	Mulayam Singh Yadav मुलायम सिंह यादव	1992
10.	Rashtriya Janata Dal (RJD) राष्ट्रीय जनता दल (राजद)	Lalu Prasad Yadav लालू प्रसाद यादव	1997
11.	Biju Janata Dal (BJD) बीजू जनता दल (बीजेडी)	Naveen Patnaik नवीन पतनाईक	1997
12.	All India Trinamool Congress (AITC) अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी)	Mamata Banerjee ममता बनर्जी	1998

13.	Jammu and Kashmir People's Democratic Party (PDP) जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी)	Mufti Mohd. Sayeed मुफ्ती मो. सईद	1999
14.	Janata Dal (United) (JD (U)) जनता दल (यूनाइटेड) (जेडी (यू))	Sharad Yadav शरद यादव	1999
15.	Janata Dal (Secular) (JD(S)) जनता दल (सेक्युलर) (जेडी(एस))	H.D. Deve Gowda एच.डी. देवेगौड़ा	1999
16.	Nationalist Congress Party (NCP) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी)	Sharad Pawar, P.A. Sangma and Tariq Anwar शरद पवार, पी.ए. संगमा और तारिक अनवर	1999
17.	Lok Janshakti Party (LJP) लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी)	Ram Vilas Paswan राम विलास पासवान	2000
18.	Telangana Rashtra Samithi (TRS) (Now, Bharat Rashtra Samithi) (BRS) तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) (अब, भारत राष्ट्र समिति) (बीआरएस)	K. Chandra Shekar Rao के. चन्द्रशेखर राव	2001
19.	Yuvajana Sramika Rythu Congress Party (YSRCP) युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी)	Y.S. Jagan Mohan Reddy वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी	2011

Sources of the Constitution at a Glance

Sl. No.	Sources	Features Borrowed
1.	Government of india Act of 1935	• Federal scheme • Office of governor • Judiciary • Public service commissions • Emergency provisions and administrative details.
2.	British Constitution	• Parliamentary government • Rule of Law • Legislative procedure • Single citizenship • Cabinet system • Prerogative writs • Parliamentary privileges and bicameralism.
3.	US Constitution	• Fundamental rights • Independence of judiciary • Judicial review • Impeachment of the president • Removal of Supreme Court and high court judges and post of vice-president.
4.	Irish Constitution	• Directive Principles of State Policy • Nomination of members to Rajya Sabha • Method of election of president.
5.	Canadian Constitution	• Federation with a strong Centre • Vesting of residuary powers in the Centre • Appointment of state governors by the Centre • Advisory jurisdiction of the Supreme Court.
6.	Australian Constitution	• Concurrent list • Freedom of trade • Commerce and inter-course • Joint sitting of the two houses of parliament.
7.	Weimar Constitution of Germany	• Emergency provisions relating to suspension of Fundamental Rights.
8.	Soviet Constitution (USSR, now Russia)	• Fundamental duties • The ideal of justice (social, economic and political) in the Preamble.
9.	French Constitution	• Republic • The ideals of liberty, equality and fraternity in the Preamble.
10.	South African Constitution	• Procedure for amendment of the Constitution and election of members of Rajya Sabha.
11.	Japanese Constitution	• Procedure established by Law.

संविधान के स्रोत एक नजर में		
क्रम सं.	**स्रोतों के नाम**	**विशेषताएं उधार ली गई**
1.	भारत सरकार अधिनियम 1935	• संघीय योजना • राज्यपाल का कार्यालय • न्यायपालिका • लोक सेवा आयोग • आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण।
2.	ब्रिटिश संविधान	• संसदीय सरकार • कानून का शासन • विधायी प्रक्रिया • एकल नागरिकता • कैबिनेट प्रणाली • विशेषाधिकार रिट • संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता।
3.	अमेरिकी संविधान	• मौलिक अधिकार • न्यायपालिका की स्वतंत्रता • न्यायिक समीक्षा • राष्ट्रपति पर महाभियोग • सर्वोच्च न्यायालय • उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद।
4.	आयरिश संविधान	• राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत • राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि।
5.	कनाडा का संविधान	• एक मजबूत केंद्र के साथ संघ • अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना • केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार।
6.	ऑस्ट्रेलियाई संविधान	• समवर्ती सूची • व्यापार • वाणिज्य और अंतर-व्यवसाय की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
7.	जर्मनी का वाइमर संविधान	• मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान।
8.	सोवियत संविधान (यूएसएसआर, अब रूस)	• प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य और न्याय का आदर्श (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक)।
9.	फ्रांसीसी संविधान	• प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता • समानता और बंधुत्व के आदर्श।
10.	दक्षिण अफरीकी संविधान	• संविधान में संशोधन • राज्य सभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया।
11.	जापानी संविधान	• कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया

Condition for Recognition as a National Party
(राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता के लिए शर्त)

- At present, a party is recognised as a national party if any of the following conditions is fulfilled:

  वर्तमान में, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है:

1. If it secures six per cent of valid votes polled in any four or more states at a general election to the Lok Sabha or to the legislative assembly; and, in addition, it wins four seats in the Lok Sabha from any state or states; or

   यदि यह लोकसभा या विधान सभा के आम चुनाव में किन्हीं चार या अधिक राज्यों में डाले गए वैध वोटों का छह प्रतिशत हासिल करता है; और, इसके अलावा, यह किसी भी राज्य या राज्यों से लोकसभा में चार सीटें जीतती है; या

2. If it wins two percent of seats in the Lok Sabha at a general election; and these candidates are elected from three states; or

   यदि वह आम चुनाव में लोकसभा में दो प्रतिशत सीटें जीतती है; और ये उम्मीदवार तीन राज्यों से चुने जाते हैं; या

3. If it is recognised as a state party in four states.

   यदि इसे चार राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

●

Conditions for Recognition as a State Party
राज्य पार्टी के रूप में मान्यता के लिए शर्तें

- At present, a party is recognised as a state party in a state if any of the following conditions is fulfilled:

  वर्तमान में, किसी पार्टी को राज्य में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है:

1. If it secures six per cent of the valid votes polled in the state at a general election to the legislative assembly of the state concerned; and, in addition, it wins 2 seats in the assembly of the state concerned; or

   यदि यह संबंधित राज्य की विधान सभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध वोटों का छह प्रतिशत हासिल करता है; और, इसके अलावा, यह संबंधित राज्य की विधानसभा में 2 सीटें जीतता है; या

2. If it secures six per cent of the valid votes polled in the state at a general election to the Lok Sabha from the state concerned; and, in addition, it wins 1 seat in the Lok Sabha from the state concerned; or

   यदि वह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध वोटों का छह प्रतिशत हासिल करता है; और, इसके अलावा, यह संबंधित राज्य से लोकसभा में 1 सीट जीतता है; या

3. If it wins three per cent of seats in the legislative assembly at a general election to the legislative assembly of the state concerned or 3 seats in the assembly, whichever is more; or

   यदि वह संबंधित राज्य की विधान सभा के आम चुनाव में विधान सभा में तीन प्रतिशत सीटें या विधानसभा में 3 सीटें, जो भी अधिक हो, जीतती है; या

4. If it wins 1 seat in the Lok Sabha for every 25 seats or any fraction thereof allotted to the state at a general election to the Lok Sabha from the state concerned; or

   यदि वह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उसके किसी अंश के लिए लोकसभा में 1 सीट जीतता है; या

❑❑❑

संविधान के संशोधन

Amendments of the Constitution

❖ **First Amendment Act (पहला संशोधन अधिनियम) 1951-**

☞ The 9th Schedule was added in which provision was made that any subject included in this list could not be subjected to judicial review by the court.
9 वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें प्रावधान किया गया कि इस सूची में शामिल किसी भी विषय की न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा (judicial review) नहीं की जा सकती।

☞ A new sub-section 15(4) was added to Article 15 empowering the States to make special provisions in favor of the socially and educationally backward classes and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.
अनुच्छेद 15 में एक नया उपखंड 15 (4) जोड़ा गया जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में विशेष प्रावधान करने के लिये राज्यों को शक्ति दी गई।

❖ **7th Amendment Act (सातवां संशोधन अधिनियम), 1956-**

☞ The provision of having a common High Court for two or more states was introduced.
दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय होने का प्रावधान पेश किया गया था।

☞ Abolition of Class A, B, C and D states - 14 States and 6 Union Territories were formed.
वर्ग ए, बी, सी और डी राज्यों का उन्मूलन- 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया।

❖ **9th Amendment Act (नौवां संशोधन अधिनियम) 1960-**

☞ Cession of Indian territory of Berubari Union (West Bengal) to Pakistan.
बेरुबारी संघ (पश्चिम बंगाल) के भारतीय क्षेत्र का पाकिस्तान को अधिग्रहण।

❖ **10th Amendment Act (10वां संशोधन अधिनियम) 1961-**

☞ Dadra, Nagar, and Haveli incorporated in the Union of Indian as a Union Territory.
दादरा, नगर और हवेली भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हैं।

❖ **12th Amendment Act (12वां संशोधन अधिनियम) 1962-**

☞ Goa, Daman and Diu incorporated in the Indian Union as a Union Territory.
गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया।

❖ **13th Amendment Act (13वां संशोधन अधिनियम) 1962-**

☞ Nagaland was formed with special status under Article 371A.
अनुच्छेद 371ए के तहत विशेष दर्जे के साथ नागालैंड का गठन किया गया था।

❖ **14th Amendment Act (14वां संशोधन अधिनियम) 1962-**

☞ Pondicherry incorporated into the Indian Union.
पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया।

☞ Union Territories of Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Goa, Daman and Diu and Puducherry were provided the legislature and council of ministers.
हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों को विधायिका और मंत्रिपरिषद प्रदान की गई।

❖ **21th Amendment Act (21वां संशोधन अधिनियम) 1967-**

☞ Sindhi language was language into 8th Schedule of Indian Constitution.
सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा थी।

❖ **26th Amendment Act (26वां संशोधन अधिनियम) 1971-**

☞ Privy Purse and privileges of former rulers of princely states were abolished.
देशी रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए।

❖ **31th Amendment Act (31वां संशोधन अधिनियम) 1972-**

☞ Lok Sabha seats were increased from 525 to 545.
लोकसभा सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 किया गया।

❖ **35th Amendment Act (35वां संशोधन अधिनियम) 1974-**

☞ The status of Sikkim as protectorate state was terminated and Sikkim was given the status of 'Associate State' of India.
सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को भारत के 'एसोसिएट स्टेट' का दर्जा दिया गया।

❖ **36th Amendment Act (36वां संशोधन अधिनियम) 1975-**

☞ Sikkim was made a full-fledged state of India.
सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था।

❖ **42th Amendment Act (42वां संशोधन अधिनियम) 1976-**

☞ Three new words were added in the Preamble of the Constitution - 'Socialist'. , 'Secular' and 'Integrity'!
संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में तीन नए शब्द जोड़े गए- 'समाजवादी' (Socialist) , 'पंथ निरपेक्ष' (Secular) तथा 'अखंडता' (Integrity) !

☞ Fundamental duties of citizens were fixed by adding a new Article 51 under Part-4A in the Constitution. This concept (Fundamental Duty) is inspired by the Constitution of the Soviet Union (East).

संविधान में भाग-4 क के तहत एक नया अनुच्छेद 51 जोड़कर नागरिकों के मूल कर्त्तव्य निर्धारित किये गए। यह संकल्पना (मूल कर्त्तव्य) सोवियत संघ (पूर्व) के संविधान से प्रेरित है।

❖ **44th Amendment Act (44वां संशोधन अधिनियम) 1978-**

☞ Article 19 (1) (f) and Article 31 related to the right to property were removed from the fundamental rights which were made a legal right through a new article 300A.
संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 (1) (च) एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों से हटा दिया गया जिसे एक नए अनुच्छेद 300 क के माध्यम से कानूनी अधिकार (Legal Right) बना दिया गया।

☞ By amending Article 74 (1), the President was empowered to return the advice given by the Council of Ministers once for reconsideration, but after that the President would be bound to accept this advice.
अनुच्छेद 74 (1) में संशोधन कर राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि मंत्रिपरिषद् द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिये एक बार लौटा सकता है , परंतु उसके बाद इस सलाह को मानने के लिये राष्ट्रपति बाध्य होगा।

❖ **52th Amendment Act (52वां संशोधन अधिनियम) 1985-**

☞ A new tenth Schedule was added providing for the anti-defection laws. Candidates can read in detail about the Tenth Schedule in the linked article.
भारत के संविधान में 52वें संशोधन की दसवीं अनुसूची को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारत के संविधान में नया शब्द 'राजनीतिक दल' शामिल हुआ।

❖ **61th Amendment Act (61वां संशोधन अधिनियम) 1989-**

☞ The voting age was decreased from 21 to 18 for both Lok Sabha and Legislative Assemblies elections.
इसमें लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।

❖ **65th Amendment Act (65वां संशोधन अधिनियम) 1990-**

☞ Multi-member National Commission for SC/ST was established and the office of a special officer for SCs and STs was removed.
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई और एससी और एसटी के लिए एक विशेष अधिकारी के कार्यालय को हटा दिया गया।

❖ **69th Amendment Act (69वां संशोधन अधिनियम) 1991-**

☞ Union Territory of Delhi was given the special status of 'National Capital Territory of Delhi.
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' का विशेष दर्जा दिया गया था।

❖ **71th Amendment Act (71वां संशोधन अधिनियम) 1992-**

☞ Konkani, Manipuri and Nepali languages were included in the Eighth Schedule of the Constitution.
कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।

❖ **73th Amendment Act (73वां संशोधन अधिनियम) 1992-**

☞ Panchayati Raj institutions were given constitutional status.
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

☞ A new Part-IX and 11th Schedule were added in the Indian Constitution to recognize Panchayati Raj Institutions and provisions related to them.
भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं और उनसे संबंधित प्रावधानों को मान्यता देने के लिए एक नया भाग-IX और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई।

❖ **74th Amendment Act (74वां संशोधन अधिनियम) 1992-**

☞ Urban local bodies were granted constitutional status.
शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

☞ A new Part IX-A and 12th Schedule were added to the Indian Constitution.
भारतीय संविधान में एक नया भाग IX-A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई।

❖ **86th Amendment Act (86वां संशोधन अधिनियम) 2002-**

☞ Elementary Education was made a fundamental right - Free and compulsory education to children between 6 and 14 years.
प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा।

❖ **92th Amendment Act (92वां संशोधन अधिनियम) 2003-**

☞ Bodo, Dogri (Dongri), Maithili and Santhali were added in the Eighth scheduleTotal official languages were increased from 18 to 22.
बोडो, डोगरी (डोंगरी), मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया, कुल आधिकारिक भाषाओं को 18 से बढ़ाकर 22 कर दिया गया।

❖ **97th Amendment Act (97वां संशोधन अधिनियम) 2011-**

☞ Co-operative Societies were granted constitutional status:
सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

☞ Right to form cooperative societies made a fundamental right (Article 19) .
सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया (अनुच्छेद 19)।

☞ A new Directive Principle of State Policy (Article 43-B) to promote cooperative societies.
सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य नीति का एक नया निदेशक सिद्धांत (अनुच्छेद 43-बी)

☞ A new part IX-B was added in the constitution for cooperative societies.
सहकारी समितियों के लिए संविधान में एक नया भाग IX-B जोड़ा गया।

❖ **100th Amendment Act (100वां संशोधन अधिनियम) 2015-**

☞ To pursue land boundary agreement 1974 between India and Bangladesh, exchange of some enclave territories with Bangladesh mentioned.
भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते 1974 को आगे बढ़ाने के लिए, बांग्लादेश के साथ कुछ एन्क्लेव क्षेत्रों के आदान-प्रदान का उल्लेख किया गया है।

☞ Provisions relating to the territories of four states (Assam, West Bengal, Meghalaya) in the first schedule of the Indian Constitution, amended.
भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में चार राज्यों (असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय) के क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया।

❖ **101th Amendment Act (101वां संशोधन अधिनियम) 2016-**

☞ Goods and Service Tax (GST) was introduced.
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) पेश किया गया था।

❖ **102th Amendment Act (102वां संशोधन अधिनियम) 2018-**

☞ Constitutional Status was granted to National Commission for Backward Classes (NCBC).
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा दिया गया था।

❖ **103th Amendment Act (103वां संशोधन अधिनियम) 2019-**

☞ A maximum of 10% Reservation for Economically Weaker Sections of citizens of classes other than the classes mentioned in clauses (4) and (5) of Article 15, i.e. Classes other than socially and educationally backward classes of citizens or the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.
अनुच्छेद 15 के खंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों के अलावा अन्य वर्गों के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण, अर्थात सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिक या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के अलावा अन्य वर्ग जनजातियाँ।

❖ **104th Amendment Act (104वां संशोधन अधिनियम) 2020-**

☞ Extended the deadline for the cessation of seats for SCs and STs in the Lok Sabha and states assemblies from Seventy years to Eighty. Removed the reserved seats for the Anglo-Indian community in the Lok Sabha and state assemblies.
लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा सत्तर साल से बढ़ाकर अस्सी कर दी गई। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया।

❖ **105th Amendment Act (105वां संशोधन अधिनियम) 2021-**

☞ According to the amendment, the President can notify the list of socially and educationally backward classes only for the purposes of the Central Government. This Central List shall be prepared and maintained by the Central Government.
संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी।

☞ Further, it enables the States and Union Territories to prepare their own list of socially and educationally backward classes.
इसके अलावा यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है।

☞ Article-338B of the Constitution mandates the Central and State Governments to consult the National Commission for Backward Classes (NCBC) on all major policy matters affecting the socially and educationally backward classes.
संविधान का अनुच्छेद- 338B केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) से परामर्श करना अनिवार्य करता है।

☞ The amendment exempts the States and Union Territories from this requirement for matters relating to the preparation of lists of socially and educationally backward classes.
संशोधन द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए इस अनिवार्यता से छूट दी गई है।

❖ **106th Amendment Act (106वां संशोधन अधिनियम) 2021-**

☞ This was the women's reservation bill which reserves one-third of all seats for women in Lok Sabha, State Legislative assemblies, and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, including those reserved for SCs and STs.
यह महिला आरक्षण विधेयक था जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जिसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।

●●●